कानपुर, सोमवार, 18 मई, 2026
वर्ष: 03, अंक: 122, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड सनातन टिप्पणी पर फिर घिरे उदयनिधि...>Pg12

लखनऊ कांड पर कानपुर बार का हल्लाबोल...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

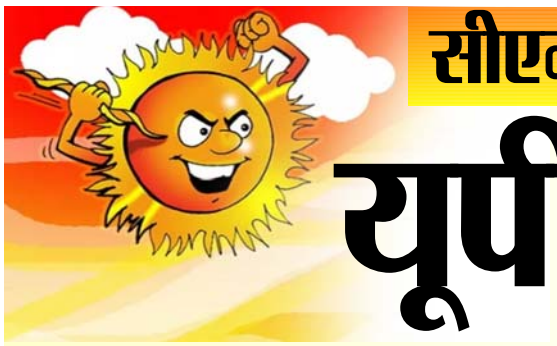

सीएम योगी ने सभी जिलों में जारी किए सख्त निर्देश

यूपी में गर्मी का रेड अलर्ट

19 से 21 मई के बीच कई जिलों में हीटवेव की आशंका, अस्पतालों से लेकर राहत एजेंसियों तक को हाई अलर्ट पर रखा गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में पड़ने वाली भीषण गर्मी और संभावित हीटवेव को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, अस्पतालों और राहत एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि लोगों को गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक 19, 20 और 21 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक पहुंच सकता है। इसके चलते कई जिलों में लू चलने और भीषण गर्मी की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मई के तीसरे सप्ताह में गर्मी का असर अधिक खतरनाक हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए विशेष वार्ड तैयार किए जाएं।

पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता, अतिरिक्त बेड और मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत रखने और एंबुलेंस सेवाओं को सक्रिय रखने को कहा गया है।

राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए राहत शिविर और अस्थायी छायादार केंद्र बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती कम करने और शहरी इलाकों में निर्बाध जलापूर्ति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और खुले में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने की बात कही है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी के दौरान लोगों को जागरूक किया जाए और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाए। आपदा प्रबंधन विभाग और राहत एजेंसियों को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। सरकार की ओर से जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को लू से बचाव, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने के उपायों की जानकारी देने की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। समय पर सावधानी न बरतने पर हीट स्ट्रोक, चक्कर, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन की पूर्व तैयारी लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार ने क्या-क्या तैयारियां शुरू कीं?

- अस्पतालों में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार
- अतिरिक्त दवाइयों और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था
- सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता
- राहत शिविर और कंट्रोल रूम सक्रिय करने के निर्देश

गर्मी से बचाव के जरूरी उपाय

- दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें
- अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लें
- हल्के और सूती कपड़े पहनें
- बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी में रखें
- चक्कर, उल्टी या तेज कमजोरी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

फर्जी डिग्री रैकेट पर कानपुर पुलिस का बड़ा शिकंजा

हैदराबाद और उन्नाव से दो आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर कमिश्नरेट की किदवई नगर पुलिस ने शिक्षा के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हैदराबाद निवासी मनीष कुमार उर्फ रवि और उन्नाव निवासी अर्जुन यादव को दबोचकर उनके कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बिना परीक्षा दिलाए

⇨ गिरोह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के नाम पर नकली माइग्रेशन सर्टिफिकेट और फर्जी मोहरें भी तैयार कर रखी थीं

हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, एलएलबी, बीफार्मा समेत कई प्रोफेशनल कोर्सों की फर्जी डिग्रियां तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराता था। गिरोह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के नाम पर नकली माइग्रेशन सर्टिफिकेट और फर्जी मोहरें भी तैयार कर रखी थीं। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल नौकरी, एडमिशन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किया जा रहा था।

किदवई नगर पुलिस के अनुसार इस मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर अब गिरोह की जड़ें दूसरे राज्यों तक फैली मिली हैं। पुलिस को मनीष कुमार के बैंक खाते में करीब 16.44 लाख रुपये के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं, जबकि अर्जुन यादव के माध्यम से करीब 20 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब इन खातों के जरिए पूरे आर्थिक नेटवर्क को खंगाल रही है।

पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी मनीष कुमार 'ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवॉर्ड यूके लंदन' नाम से एक संस्था संचालित करता था। इसके जरिए वह देश के अलग-अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास करता था। पुलिस को आशंका है कि इसी नेटवर्क का इस्तेमाल फर्जी डिग्री कारोबार को फैलाने में किया गया।

कानपुर पुलिस का कहना है कि गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस साइबर और बैंकिंग रिकॉर्ड के जरिए पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इस कार्रवाई ने शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने वाले संगठित गिरोहों की गंभीरता को उजागर कर दिया है।

केडीए का बुलडोजर गरजा

48 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

53 बीघा में नोटिस जारी, अवैध निर्माणकर्ताओं में मचा हड़कंप

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ एक बार फिर बड़ा बुलडोजर अभियान चलाते हुए लगभग 48 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं करीब 53 बीघा क्षेत्र में चल रही अवैध प्लाटिंग पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं और अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया।

केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौषिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-4 के विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई।

केडीए टीम ने आराजी संख्या-109, 122 व अन्य आराजियों, सरकारी नाले तथा मथुरापुर योजना के पीछे लगभग 48 बीघा क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, नाले, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, इंटरलॉकिंग, सीवर लाइन सहित कई निर्माणों को दो जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान विशाल, लल्लू व अन्य लोगों द्वारा विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया। ओएसडी डॉ रवि प्रताप सिंह ने साफ कहा कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके अलावा केडीए ने लगभग 53 बीघा क्षेत्र में चल रही अन्य अवैध प्लाटिंग पर नोटिस जारी किए हैं। इनमें कैलाश लखमानी व अन्य द्वारा भौंती सुरसर, कानपुर में करीब 18 बीघा तथा इंद्रा नगर फेज-1, फिक्की चौराहा क्षेत्र में लगभग 35 बीघा में की जा रही प्लाटिंग शामिल है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान अवर अभियंता अतुल चतुर्वेदी समेत संबंधित थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही।

केडीए उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्लाट या भूखंड को खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसका ले-आउट और मानचित्र स्वीकृत होने की जानकारी अवश्य कर लें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

विद्यार्थी जी के बलिदान स्थल पर बनेगा भव्य स्मारक

सांसद रमेश अवस्थी ने किया निरीक्षण, प्रताप प्रेस भवन के संरक्षण का भी दिया भरोसा

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृतियों को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सांसद रमेश अवस्थी ने शनिवार को चौबेगोला स्थित विद्यार्थी जी के बलिदान स्थल एवं फीलखाना स्थित ऐतिहासिक प्रताप प्रेस भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों स्थलों के जीर्णोद्धार और संरक्षण का आश्वासन देते हुए बलिदान स्थल पर भव्य स्मारक निर्माण की घोषणा की।

शनिवार सुबह प्रताप वैश्विक संस्थान का प्रतिनिधिमंडल सांसद से उनके आवास पर मिला और विद्यार्थी जी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की मांग उठाई। इसके बाद शाम को सांसद स्वयं चौबेगोला और फीलखाना पहुंचे तथा मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने वहीं पर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।

सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी केवल पत्रकारिता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद और सामाजिक सौहार्द के भी प्रतीक रहे हैं। उनके बलिदान स्थल को ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए वहां स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही प्रताप प्रेस भवन को भी संरक्षित कर उसकी ऐतिहासिक विरासत को बचाया जाएगा।

प्रताप वैश्विक संस्थान के अध्यक्ष डॉ. सुधांशु त्रिपाठी ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत विष्णु त्रिपाठी के नेतृत्व में संस्थान पिछले लगभग डेढ़ दशक से इस मांग को लगातार उठा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जी की स्मृतियों को संरक्षित करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

महासचिव भारतेंदु पुरी ने उम्मीद जताई कि इस बार वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी और शहर को उसकी ऐतिहासिक धरोहर वापस मिलेगी। समन्वय प्रमुख शांतनु चैतन्य ने कहा कि कानपुर के गौरवशाली इतिहास और विद्यार्थी जी के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर डॉ. रमेश वर्मा, उमेश शुक्ल, सुनील साहू, अरुण पांडेय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

जिंदगी की जंग के बीच बंधे सात फेरे, अस्पताल वार्ड बना मंडप

» आग के हादसे से टूटी खुशियां, लेकिन दूल्हे के अटूट प्रेम ने अस्पताल में रच दिया इतिहास

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। खुशियों से गूंजने वाला घर अचानक चीख-पुकार में बदल गया, मेहंदी लगे हाथ दर्द से कराह उठे और शादी की तैयारियों के बीच मातम जैसा माहौल छा गया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के आगे प्रेम ने हार नहीं मानी। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही दुल्हन के साथ दूल्हे ने अस्पताल के वार्ड में सात फेरे लेकर रिश्ते की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं।घाटमपुर क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में शाम को मेहंदी की रस्म के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। बताया गया कि कार्यक्रम के बीच अचानक सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी। अफरा-तफरी के दौरान चूल्हे पर रखी तेल की गर्म कढ़ाई पलट गई, जिससे दुल्हन श्वेता समेत करीब 12 लोग झुलस गए। कुछ ही पलों में शादी की खुशियां दर्द में बदल गईं। परिजन घायलों को अस्पताल लेकर भागे और गुरुवार को होने वाली शादी टाल दी गई।

हादसे के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अस्पताल के बेड पर दर्द से तड़प रही दुल्हन को यह चिंता सता रही थी कि अब शायद उसकी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन कानपुर के तात्या टोपे नगर निवासी दूल्हे ने ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। दूल्हे ने साफ कहा कि शादी हर हाल में श्वेता से ही होगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूल्हे के इस फैसले के बाद दोनों परिवारों की सहमति से अस्पताल प्रशासन से वार्ड में विवाह कराने की अनुमति मांगी गई।

मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने भी पूरा सहयोग किया। देर रात अस्पताल का वार्ड ही मंडप में बदल गया। बेड पर बैठी दुल्हन के सामने दूल्हे ने सिंदूर भरकर वैवाहिक रस्में निभाईं। परिवार के लोग, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इस भावुक पल के साक्षी बने। अस्पताल के माहौल में जब शहनाई की जगह मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं, तब भी रिश्तों की गर्माहट और प्रेम की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। शादी की इस अनोखी तस्वीर ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। कई लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा विवाह देखा, जहां दर्द के बीच भी रिश्तों की मजबूती और इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। हादसे से मायूस परिवार के चेहरों पर भी इस शादी के बाद राहत और सुकून नजर आया।

अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में भड़के वकील

लखनऊ कांड पर कानपुर बार का हल्लाबोल

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। लखनऊ में अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को कानपुर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन का नेतृत्व कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी और महामंत्री विनय कुमार मिश्रा ने किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि लखनऊ में जिस तरह अधिवक्ताओं के साथ दंडात्मक कार्रवाई की गई, वह बेहद निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों के

➪ **डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार से माफी व अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग**

खिलाफ है। उन्होंने मांग उठाई कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के साथ हुए व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जिन अधिवक्ताओं को नुकसान पहुंचा है, उनकी भरपाई सुनिश्चित करे।

अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि प्रदेशभर की कचहरियों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध नहीं हैं। गर्मी, बारिश और सर्दी के मौसम में अधिवक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को सभी न्यायालय परिसरों में उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि अधिवक्ता निर्बाध रूप से न्यायिक कार्य कर सकें और न्याय मांगने आने वाले लोगों को भी दिक्कत न हो। बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता कठिन परिस्थितियों में भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन सरकार उनके सम्मान की रक्षा करने के बजाय उन पर लाठियां चलवा रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज इस कार्रवाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिवक्ताओं की समस्याओं और हितों की लगातार अनदेखी की गई, तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अधिवक्ता सरकार के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

देह व्यापार पर रावतपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

➪ **महिला समेत तीन गिरफ्तार, नागेश्वरम अपार्टमेंट के पास चल रहा था गोरखधंधा**

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रावतपुर थाना पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

एसीपी कल्याणपुर के निर्देशन में रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय की टीम लगातार क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान डायल-112 पर सूचना मिली कि केडीएमए स्कूल के पीछे नागेश्वरम अपार्टमेंट के पास स्थित एक मकान में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से मोहित यादव निवासी आदर्श नगर रावतपुर, शरीफ निवासी नई बस्ती मस्वानपुर तथा सुनीता अग्निहोत्री निवासी पुरानी बस्ती काकादेव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, तीनों लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। बरामद सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कमलेश राय, उपनिरीक्षक नौशाद अहमद, विकास यादव, रोहित सिंह, राजकुमार, सत्यम चौहान, पंकज शर्मा, उमेश सिंह तथा महिला उपनिरीक्षक काजल रैकवार सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।

फर्जी जीएसटी फर्म से करोड़ों की टैक्स चोरी का खुला राज

कागजों में चल रही कंपनी ने सरकार को लगाया करोड़ों का चूना, स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी करने का बड़ा मामला सामने आया है। राज्यकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि कागजों में संचालित की जा रही एक फर्म के जरिए करोड़ों रुपये की फर्जी खरीद दिखाकर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया गया। मामले में स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, पीके इंटरप्राइजेज नामक फर्म के संचालक अनिल कुमार के खिलाफ राज्यकर विभाग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में सामने आया कि फर्म का जीएसटी पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया गया था। विभागीय अधिकारियों ने जब फर्म के पते का सत्यापन किया तो वहां किसी प्रकार का व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं मिला।

जांच के दौरान भवन स्वामी से पूछताछ की गई तो उसने भी किरायानामा फर्जी बताया। इतना ही नहीं, जीएसटी पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर भी गलत निकला। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी फर्म केवल कागजों पर खड़ी की गई थी ताकि

टैक्स चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए बड़ा आर्थिक खेल किया जा सके।

राज्यकर विभाग के अनुसार, आरोपी ने करीब 40 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दर्शाकर लगभग 3.74 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फर्जी बिलिंग और आईटीसी क्लेम के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाने का यह संगठित तरीका बनता जा रहा है। मामले की शिकायत के बाद स्वरूप नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संभावित फर्जी फर्मों की भी पड़ताल कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

कैसे होता है फर्जी आईटीसी खेल?

फर्जी फर्म बनाकर कागजों में खरीद-बिक्री दिखाई जाती है। इसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर टैक्स देनदारी कम कर दी जाती है। असली कारोबार न होने के बावजूद सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है।

जांच में सबसे बड़ी पकड़ क्या रही?

राज्यकर विभाग की फिजिकल वेरिफिकेशन में फर्म का अस्तित्व ही नहीं मिला। भवन स्वामी द्वारा किरायानामा फर्जी बताना और मोबाइल नंबर गलत निकलना जांच का सबसे मजबूत आधार बना, जिससे पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया।

क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले?

ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेजों से कंपनियां बनाई जा रही हैं। कमजोर सत्यापन और आईटीसी व्यवस्था की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर टैक्स चोरी के संगठित गिरोह सक्रिय हो गए हैं।

भीषण गर्मी से झुलसा कानपुर

43 डिग्री पार पहुंचा पारा तीन दिन और सताएगी लू

» सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने 20 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर में भीषण गर्मी और हीटवेव ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 27.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र और भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रहने के कारण वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने 18 से 20 मई तक लू का प्रकोप जारी रहने की चेतावनी दी है।

रविवार को हवा की औसत गति 6.2 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चली।

सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 39 प्रतिशत और न्यूनतम 22 प्रतिशत रहने से वातावरण में नमी बेहद कम रही, जिससे गर्मी और अधिक चुभन भरी महसूस हुई। दोपहर के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी।

सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, किसानों और बाहर काम करने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी के मामले बढ़ सकते हैं। लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। खेतों में सुबह या शाम के समय ही कार्य करने और पशुओं के लिए पर्याप्त पानी व छांव की व्यवस्था करने की अपील की गई है।

युवा अधिकार पंचायत में 219 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ

» गोविंद नगर में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरा गया

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। गोविंद नगर क्षेत्र में महानगर कांग्रेस की ओर से ÷युवा अधिकार पंचायत÷ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने की, जबकि एआईसीसी सदस्य एवं किदवई नगर कोऑर्डिनेटर विकास अवस्थी ने संयोजन और संचालन संभाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताते हुए 219 युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

ढोल-नगाड़ों और कांग्रेस समर्थक नारों के बीच पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम संयोजक विकास अवस्थी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती फीस और लगातार रद्द हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं से युवा वर्ग निराश है। कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी।

इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष मोहित सविता, प्रभाकर पाण्डेय, अनुराग पाल और ऋषि तिवारी ने भी युवाओं की समस्याओं पर अपने विचार रखे। जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि देश में परिवर्तन का इतिहास युवाओं के आंदोलनों से जुड़ा रहा है और अब फिर युवाओं के एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए विकास अवस्थी की सराहना की।

कार्यक्रम में जेपी पाल, आलोक मिश्रा, हरप्रकाश अग्निहोत्री, नौशाद आलम मंसूरी, हरीश बाजपई, रितेश यादव, पदम मोहन मिश्रा, राकेश साहू, धर्मेंद्र सिंह, राम नवल, रामस्वरूप तिवारी, फजल खान, रवि तिवारी, राज किशोर वर्मा, रमाकांत शर्मा, मदन मोहन राखरा, आनंद वर्मा, विनोद अवस्थी, नागेंद्र यादव, नीरज तिवारी, इमराना खान, जफर शाकिर मुन्ना, कमलाकांत तिवारी और राजेश खन्ना सहित कई लोग मौजूद रहे।

कानपुर-सागर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम, एंबुलेंस तक फंसी रही

बिनगवां से बिधनू तक रेंगते रहे वाहन, घंटों सड़क पर परेशान रहे लोग

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। बिधनू थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह कानपुर-सागर हाईवे पर लगा भीषण जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। सुबह करीब नौ बजे वाहनों का दबाव बढ़ते ही बिनगवां से बिधनू तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए और हजारों लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को उठानी पड़ी। कई एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं, जिससे लोगों में नाराजगी दिखी।

सुबह दफ्तर और स्कूल का समय होने के कारण हाईवे पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। ट्रक, बस, कार और ई-रिक्शा एक-दूसरे के बीच फंस गए। कई जगह लोगों ने गलत दिशा से वाहन निकालने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। तेज धूप और उमस के बीच लोग घंटों जाम खुलने का इंतजार करते रहे।

स्थानीय लोगों का कहना था कि इस मार्ग पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े भारी वाहन और धीमी रफ्तार से चल रहे ट्रक जाम की बड़ी वजह बने। कई वाहन चालकों ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

सूचना मिलते ही बिधनू पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए एक-एक कर वाहनों को निकलवाया और ट्रैफिक को सामान्य कराने का प्रयास किया। करीब कई घंटे बाद हाईवे पर यातायात आंशिक रूप से सुचारू हो सका। घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि सुबह के समय हाईवे पर वाहनों का दबाव अधिक होने से रमईपुर और बिनगवां क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल करा दिया है।

सम्पादकीय

खाड़ी संघर्ष के असर से बढ़ी महंगाई की मार

संयुक्त राष्ट विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की पश्चिम एशिया युद्ध से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करने वाली रिपोर्ट के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी में ईरान-अमेरिकी युद्ध से उपजी परिस्थितियों के चलते भारत में और 25 लाख लोग गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं। साथ ही मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका पैदा हो गई है। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं। इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया-प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है। दरअसल, आज भी भारत करीब 90 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर आश्रित है। हम कच्चे तेल का 40 फीसदी से अधिक और रसोई गैस का 90 फीसदी आयात पश्चिम एशिया से करते हैं। साथ ही हम अपने उर्वरकों का 40 फीसदी हिस्सा युद्धग्रस्त पश्चिमी एशिया से आयात करते हैं। एलएनजी की कीमतों में वृद्धि से कोयला आधारित बिजली पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर व्यापार व आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई। आशंका है कि संघर्ष से रेमिटेंस में भी कमी आएगी।निस्संदेह, मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी की वजह से आयातित तेल आदि की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे आयात मूल्य में वृद्धि व निर्यात का नुकसान बढ़ा है। असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। वहीं खाद की आपूर्ति में बाधा का असर खरीफ की फसल पर पड़ने की आशंका है। इस सब के चलते बढ़े दामों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर हो रहा है, जिसका रोजगार और आय के मामले में असर बड़ी आबादी पर नजर आ रहा है। हाल ही में नोएडा और मानेसर में श्रमिक असंतोष को इसकी परिणति के रूप में महसूस किया जा सकता है। दरअसल, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आर्थिक परेशानियों के चलते आम आदमी अब अपने जरूरी खर्चों में कटौती कर रहा है। वजह है उसकी आय के साधन सीमित होना। वहीं निम्न आय वर्ग के लोगों में इससे भरण-पोषण का संकट पैदा हो रहा है। श्रमिक असंतोष के बीच आक्रोश उभरा कि महंगाई के अनुपात में उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, फलतः जीवनयापन कठिन होता जा रहा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया कि मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4 हो गई है, जिसकी वजह पश्चिमी एशिया से उपजा संकट बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास सिरे क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। यदि कदम प्रभावकारी हैं तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। वास्तव में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को महंगाई का मुख्य कारण बताया जा रहा है। यद्यपि सरकार की दलील है कि खुदरा महंगाई दर केंद्रीय बैंक की रेड लाइन चार फीसदी से नीचे है। लेकिन वास्तव में स्थिर आय के चलते महंगाई अधिक महसूस की जा रही है। लेकिन लोगों की चिंता है।

यूरोप क्यों माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार कर रहा है

एक गहन संरचनात्मक बदलाव

(निखिलेश मिश्रा, पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी)

हाल के वर्षों में, यूरोप के सार्वजनिक संस्थानों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और नीतिगत क्षेत्रों में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकारें, नगर प्रशासन और नियामक संस्थाएँ लंबे समय से उपयोग किए जा रहे स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम - विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों जैसे विंडोज़, ऑफिस औरU Azure पर अपनी निर्भरता पर सवाल उठा रहे हैं। यह बदलाव अचानक नही हुआ है, न ही यह केवल तकनीकी है; बल्कि यह कई स्तरों पर उत्पन्न चिंताओं का परिणाम है, जिनमें डिजिटल संप्रभुता, आर्थिक नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार क्षेत्र और दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता जैसे कारक शामिल हैं।

इस पुनर्विचार के केंद्र में डिजिटल संप्रभुता÷ की अवधारणा है। यूरोपीय देश अब विदेशी तकनीकी प्रदाताओं विशेषकर अमेरिकी कंपनियों पर अपने महत्वपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के लिए निर्भर रहने को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जैसे सॉफ्टवेयर सरकारों के कार्यों, शिक्षा प्रणालियों, रक्षा नेटवर्क और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गहराई से समाहित हैं। यह निर्भरता कई गंभीर प्रश्न उठाती है– डेटा पर अंतिम नियंत्रण किसका है? यह किस कानूनी ढांचे के अंतर्गत आता है? और यदि भू-राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? यह चिंताएँ विशेष रूप से अमेरिकी कानूनों, जैसे ष्ट्रस्रुष्ठ ष्ह्ल, के संदर्भ में और गंभीर हो जाती हैं, जो अमेरिकी कंपनियों को यूरोप में संग्रहीत डेटा (स्टोर डेटा) तक भी पहुँच प्रदान कर सकता है। ब्रुसेल्स, बर्लिन और पेरिस के नीति-निर्माताओं के लिए यह एक संरचनात्मक जोखिम है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।आर्थिक पहलू भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निजी स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के लाइसेंस शुल्क यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से लगातार बाहर जाते रहते हैं, जो अंततः वित्तीय दबाव और तकनीकी निर्भरता दोनों पैदा करते हैं। एक बार जब कोई संस्था माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों पर आधारित कार्यप्रणाली विकसित कर लेती है, तो उससे बाहर निकलना महंगा और जटिल हो जाता है। यूरोपीय सरकारें इसे एक रणनीतिक कमजोरी के रूप में देखने लगी हैं। इसलिए वे ओपन-सोर्स विकल्पों जैसे Linu& आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, LibreOffice और अन्य समुदाय-आधारित (कम्युनिटी बेस्ड) प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रही हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि स्थानीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाए, जिससे यूरोप के भीतर नवाचार और विकास को प्रोत्साहन मिले।साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यद्यपि माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा पर भारी निवेश करता है, फिर भी एक ही प्रमुख प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता स्वयं एक प्रणालीगत जोखिम बन सकती है। विंडोज़ में कोई भी कमजोरी लाखों प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न होता है। इस कारण यूरोपीय एजेंसियाँ विविधता को एक सुरक्षा रणनीति के रूप में अपनाने पर विचार कर रही हैं।

ओपन-सोर्स सिस्टम अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके कोड का निरीक्षण, संशोधन और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन किया जा सकता है जो संवेदनशील सरकारी कार्यों के लिए आकर्षक है।यह मुद्दा गहराई से राजनीतिक भी है। यूरोप लंबे समय से डिजिटल क्षेत्र में अपनी नियामक शक्ति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है जैसे GDPR और Digital Markets Act के माध्यम से कर रहा है। लेकिन केवल नियमन पर्याप्त नहीं है यदि उसका तकनीकी नियंत्रण किसी और के हाथ में हो। नीति-निर्माताओं को यह एहसास हो रहा है कि वास्तविक स्वायत्तता के लिए बुनियादी तकनीकी ढांचे पर नियंत्रण आवश्यक है। इसी दिशा में ÷यूरोपीय स्टैक÷ विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं- ऐसे एकीकृत सॉफ्टवेयर और क्लाउड सिस्टम जो यूरोपीय कानूनों और मूल्यों के अनुसार संचालित होते हों। Gaia-X जैसी परियोजनाएँ इसी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ से दूर जाना इतना आसान नहीं है। म्यूनिख जैसे शहरों में Linu& अपनाने के प्रयासों को पहले भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है- जैसे संगतता (कम्पेटिबिल्टी) की समस्याएँ, उपयोगकर्ता को असुविधा और अप्रत्याशित लागत।

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए वरदान है ‘ नो-कुक’ आहार

आज का भारत एक जटिल और चुनौतीपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। एक ओर हम वैश्विक अस्थिरता के कारण एलपीजी सहित सभी आयातित सामग्रियों की आसमान छूती कीमतों से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर हम मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी साइलेंट पेंडेमिक यानी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भविष्य की महंगी तकनीकों की ओर देख रही है, तब इसका वास्तविक और प्रभावी समाधान हमारे पूर्वजों के उन बिना आग वाले चूल्हों में छिपा हो सकता है। आधुनिक भारतीय घरों में सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक नीली लौ पर निर्भरता एक अनिवार्य मजबूरी बन गई है, लेकिन भू-राजनीतिक तनावों के कारण ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल रहा है।

लेखक परिचय

प्रो. दिनेश चन्द्र राय, देश के एक अग्रणी खाद्य वैज्ञानिक, बीएचयू (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) के सीनियर प्रोफेसर तथा वर्तमान में बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तीन दशकों से ज्यादा का उनका व्यापक अनुसंधान और लेखन मुख्य रूप से कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, पारंपरिक पोषण विज्ञान, सतत विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

प्रो. दिनेश चन्द्र राय, कुलपति, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय-समय पर, विशेषकर अपने मन की बात संबोधनों (119वे और 132वे एडिशन) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी की पुस्तक विमोचन के अवसरों पर, देशवासियों से अपनी सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खाद्य तेलों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग को कम करने का सीधा आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी आह्वान को धरातल पर उतारने का सबसे व्यावहारिक और प्रभावी माध्यम हमारा यह नो-कुक पारंपरिक आहार ही है, जिसके माइक्रो लेवल पर अद्भुत बहुआयामी लाभ हैं। सबसे पहले, चूंकि भारत वर्तमान में अपनी जरूरत का लगभग 60त्न खाद्य तेल आयात करता है, इसलिए तेल की खपत कम होने से देश का यह विशाल आयात बिल घटेगा और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार की सीधी बचत होगी। दूसरा, बिना आग के तैयार होने वाले इन व्यंजनों को अपनाने से घरेलू एलपीजी गैस की खपत कम होगी, जिससे सीधे तौर पर देश का ऊर्जा आयात और राजकोषीय घाटा नियंत्रित होगा। तीसरा, यह बदलाव सीधे तौर पर फिट इंडिया अभियान को गति देगा क्योंकि डीप-फ्राई और अत्यधिक तेल वाले भोजन से होने वाली बीमारियाँ जैसे, फैटी लीवर, हृदय रोग और मोटापा कम होगा, जिससे देश के चिकित्सा ढांचे पर दबाव घटेगा। अंततः, सत्तू (चना/जौ/बाजरा) और चूड़ा (धान) जैसे स्थानीय अनाजों की मांग बढ़ने से हमारे छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिलेगा। हमारी प्राचीन भारतीय खाद्य प्रणाली केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति के बीच एक अद्भुत संतुलन का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अनुभव से ऐसे व्यंजनों को विकसित किया जो शरीर को पोषण भी देते थे और पर्यावरण को सुरक्षा भी। यह प्रणाली ऋतु (प्राकृतिक नियम) पर आधारित थी, जहाँ भोजन को उसकी मौलिक शक्ति के साथ ग्रहण किया जाता था।

हमारे पूर्वजों ने मिट्टी की तासीर, मौसम के बदलाव और शरीर की आवश्यकताओं को समझकर सत्तू, चूड़ा और अंकुरित अनाज जैसे अमृत तुल्य आहार की रचना की। यह प्रणाली आज के सस्टेनेबल यानी टिकाऊ जीवन का सबसे उत्कृष्ट और पुराना उदाहरण है। इस संकट का सबसे व्यावहारिक समाधान हमारे पारंपरिक नो-कुक भोजन जैसे चूड़ा-दही और सत्तू में निहित है, जो घरेलू ईंधन की खपत में शत-प्रतिशत की कमी लाते हैं। यदि एक परिवार दिन में केवल एक बार पकाए हुए भोजन के स्थान पर इन पारंपरिक व्यंजनों को अपनाए, तो एक मानक एलपीजी सिलेंडर निश्चित ही ज्यादा दिन चलेगा। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों की यह खाद्य प्रणाली लचीलेपन और स्थिरता के लिए ही विकसित की गई थी। उदाहरण के तौर पर, चूड़ा अपनी प्राथमिक प्रोसेसिंग के दौरान ही तैयार हो जाता है और उपभोक्ता तक पहुँचने के बाद इसे किसी सक्रिय कुकिंग की आवश्यकता नहीं होती। आज जहाँ पूरी दुनियाप्रोबायोटिक के नाम पर पेट के स्वास्थ्य के लिए तरह-तरह की महंगी गोलियाँ और सप्लीमेंट्स बेच रही है, वहीं हमारे पास सदियों पुराना और सस्ता समाधान उपलब्ध है। चूड़ा-दही का संयोजन फर्मेंटेड दही और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मेल से एक ऐसा प्रीबायोटिक-प्रोबायोटिक सिनर्जी पैदा करता है, जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब जाकर पहचान रहा है। इसके अलावा, सत्तू, भारतीय सुपरफूड, पोषक तत्वों का खजाना है। अक्सर सत्तू को गरीबों का व्हे प्रोटीन कहकर अपमानित किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह अपनी सुपाच्य प्रकृति, प्रचुर मात्रा में मौजूद फाइबर और समग्र पोषण के कारण आधुनिक व्हे प्रोटीन से कहीं अधिक और श्रेष्ठ है। इसे रेत में भूनकर तैयार किया जाता है, जिससे इसके गुण सुरक्षित रहते हैं और इसे बिना गैस जलाए तुरंत उपयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज भी इसी जीरो-फ्यूल क्रांति का हिस्सा हैं, जो एंजाइम्स और विटामिन्स की उच्च मात्रा प्रदान करते हैं। दैनिक जीवन में किए गए ये छोटे-छोटे और व्यावहारिक बदलाव माइक्रो लेवल पर देश के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।

57 नए पुलिसकर्मियों की तैनाती से बिल्हौर की पुलिसिंग हुई मजबूत

कस्बे के 25 वार्ड और चार ग्राम पंचायतों को सात बीटो में बांटा गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर थाने की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 2025 बैच के 57 नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें सात महिला कांस्टेबल और 50 पुरुष कांस्टेबल शामिल हैं। नई तैनाती के बाद कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कस्बा चौकी क्षेत्र के 25 वार्डों और चार ग्राम पंचायतों बीबीपुर, सुभानपुर, बरौली और बिल्हौर देहात को पहले से सात बीटों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक बीट में एक बीट प्रभारी की जिम्मेदारी तय थी। अब नई व्यवस्था के तहत हर बीट प्रभारी के साथ दो-दो सिपाहियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं बिल्हौर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में भी प्रभारियों के साथ नए सिपाहियों को जोड़ा गया है, जिससे पुलिस बल ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई तैनाती से क्षेत्र में गश्त बढ़ेगी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी और लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। बिल्हौर कस्बा चौकी प्रभारी कपिल ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है। कस्बे में अलग-अलग टोलियों के लिए ड्यूटी चार्ट भी तैयार किया गया है।

➪ हर बीट प्रभारी के साथ अब दो-दो सिपाहियों की तैनाती

कोतवाल सुधीर की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधी भूमिगत

बिल्हौर कोतवाली का चार्ज संभाले इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को अभी चार महीने ही हुए हैं, लेकिन कम समय में उन्होंने अपराधियों, वारंटियों और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपनी अलग पहचान बना ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके कार्यकाल में अब तक सबसे ज्यादा आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई हुई है। लगातार दबिश और सख्त कार्रवाई के चलते सड़क पर उत्पात मचाने वाले और अवैध गतिविधियों में शामिल कई लोग भूमिगत हो गए हैं। कस्बे में बढ़ी पुलिस सक्रियता और लगातार हो रही चेकिंग से असामाजिक तत्वों में खौफ का माहौल है। वहीं कोतवाल सुधीर कुमार का कहना है कि अपराध कैसा भी हो और किसी ने भी किया हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

अरौल पुलिस ने बरामद किए 19 खोए मोबाइल, मालिकों को लौटाए

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। अरौल थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 19 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।थाना प्रभारी जनार्दन सिंह यादव के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी निगरानी और लगातार प्रयासों के जरिए मोबाइल फोन तलाश किए। एसीपी सुभाष चंद्र की मौजूदगी में सभी मोबाइल धारकों को थाने बुलाकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराई गई और उनके मोबाइल सुपुर्द किए गए।

पुलिस के मुताबिक, ये मोबाइल फोन बाजार, टैक्सी, दुकानों, खेतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कहीं गिर गए थे या लोग उन्हें भूल गए थे। मोबाइल गुम होने के बाद संबंधित लोगों ने अरौल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सर्विलांस टीम ने तकनीकी सहायता से उनकी तलाश शुरू की। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें फोन मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। फोन के साथ जरूरी डेटा वापस मिलने पर लोगों ने अरौल पुलिस की कार्यशैली की सराहना की।

एसीपी सुभाष चंद्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते तकनीकी माध्यमों से उसकी तलाश की जा सके। उन्होंने सर्विलांस टीम के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है।

➪ सर्विलांस टीम की मदद से तीन लाख से अधिक कीमत के फोन हुए बरामद

➪ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिले, पुलिस का जताया आभार

गंगा में डूबती महिला को बचाने कूदा छात्र, मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर के सरैया घाट पर रविवार को गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। डूब रही महिला को बचाने के प्रयास में एक छात्र की जान चली गई, जबकि महिला समेत दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

रायपुरवा के कारवालो नगर निवासी 24 वर्षीय राज चौरसिया परिवार के साथ गंगा स्नान करने सरैया घाट आया था। स्नान के दौरान परिवार की महिला सदस्य दीपांती चौरसिया गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। उन्हें बचाने के लिए राज तुरंत गंगा में कूद पड़ा, लेकिन तेज बहाव में वह खुद भी फंस गया।इसी बीच अंबर उर्फ गुन्नू भी मदद के लिए नदी में उतर गया और धारा की चपेट में आ गया। घाट पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दीपांती और अंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में राज को भी बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवराजपुर भेजा गया। हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया, लेकिन कल्याणपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज इंटरमीडिएट का छात्र था और पिता दिनेश चौरसिया की निकिल पॉलिश की दुकान में हाथ बंटाता था। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है।

मृतक राज चौरसिया

➪ सरैया घाट पर हादसा, दो लोगों की बची जान

छात्र राज की दिलेरी को सलाम, मिलना चाहिए वीरता पुरस्कार

जिस तरह से इंटर के छात्र ने डूबती हुई एक महिला को बचाने में खुद का बलिदान कर दिया। वह बहुत ही बहादुरी का कार्य है। ऐसा कार्य बिरले लोग ही कर पाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि राज के परिवारिजनों को राज की बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीरता पुरस्कार देने के लिए शासन से संस्तुति की जानी चाहिए।

हाईवे पर पलटा लोहे की क्वायल से लदा ट्रक, टला बड़ा हादसा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लोहे की क्वायल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा अरौल थाना क्षेत्र के बकोठी गांव के पास हुआ। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के मुताबिक ट्रक जमशेदपुर से लोहे की क्वायल लेकर गाजियाबाद जा रहा था। सुबह करीब छह बजे बकोठी गांव के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक सड़क किनारे पलट गया। ट्रक पलटने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा।

चालक अनिल कुमार ने बताया कि पीछे से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रक असंतुलित हो गया। हादसे में चालक सुरक्षित बच गया, जबकि खलासी सुरेंद्र को मामूली चोटें आईं। दोनों राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। सूचना मिलते ही अरौल थाना पुलिस उपनिरीक्षक ओमप्रकाश के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से पलटे ट्रक को सड़क किनारे हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य कराया गया। थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह चालक का वाहन पर नियंत्रण खोना सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है।

➪ बकोठी गांव के पास सुबह हुआ हादसा, चालक-खलासी सुरक्षित

➪ हाइड्रा की मदद से हटवाया गया ट्रक, यातायात कराया गया बहाल

हाईवे पर फिर मौत का तांडव, तेज रफ्तार ने छीन ली 10 जिंदगियां

ईसानगर हादसे पर सीएम योगी सख्त, राहत-बचाव के दिए निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। ईसानगर क्षेत्र में ऊंच गांव और भरेहटा के बीच सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। तेज रफ्तार ट्रक और मैजिक की आमने-सामने की भीषण टक्कर में मैजिक सवार 10 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतकों में तीन लोगों की शिनाख्त होने की जानकारी सामने आई है।

घटना स्थल पर डीएम व एसपी

घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचकर घायलों के समुचित इलाज और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दिए। वहीं प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी हादसे को बेहद पीड़ादायक बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

इस हादसे के बाद एक बार फिर लखीमपुर-सिसैया रोड नेशनल हाईवे की बदहाल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे हाईवे पर डिवाइडर न होने और ओवरलोड वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते आए दिन भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं। हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक कार्रवाई और सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन बाद में संबंधित विभाग फिर लापरवाह हो जाते हैं। लोगों ने हाईवे पर डिवाइडर निर्माण और ओवरलोडिंग पर स्थायी रोक लगाने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।

जहरीले कार्बोफ्यूरान ने छीन ली गिद्धों की 'उड़ान'

दुधवा तराई में 25 गिद्धों की मौत से मचा हड़कंप, जांच रिपोर्ट में खतरनाक पेस्टीसाइड की पुष्टि

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। तराई के जंगलों में मृत मिले 25 गिद्धों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों को झकझोर दिया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन गिद्धों की मौत अत्यंत जहरीले पेस्टीसाइड ÷कार्बोफ्यूरान÷ के कारण हुई। रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों ने उन कुत्तों के शवों को खाया था, जिनके शरीर में यह रसायन मौजूद था।

विशेषज्ञों के मुताबिक कार्बोफ्यूरान कार्बोमेट श्रेणी का बेहद खतरनाक कृषि रसायन है, जिसका उपयोग कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है।

इसकी थोड़ी सी मात्रा भी पक्षियों और वन्यजीवों के लिए घातक साबित हो सकती है। कई देशों और राज्यों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध या कड़े नियंत्रण लागू हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसके अवैध इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रहती हैं।मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक संजय पाठक ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया। वन विभाग की टीम ने मौके से नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे थे। अब रिपोर्ट में जहरीले रसायन की पुष्टि होने के बाद विभागीय सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि आखिर यह रसायन कुत्तों के शवों तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे लापरवाही थी या कोई सुनियोजित गतिविधि।यह पूरा इलाका विश्वप्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व के प्रभाव क्षेत्र में आता है, जो नेपाल सीमा से सटा संवेदनशील वन क्षेत्र है। यहां गिद्धों समेत कई दुर्लभ पक्षी और वन्यजीव पाए जाते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि गिद्ध प्रकृति के ÷सफाईकर्मी÷ होते हैं, जो मृत जीवों को खाकर संक्रमण फैलने से रोकते हैं। बड़ी संख्या में उनकी मौत पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। घटना के बाद पर्यावरण संगठनों और वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं ने जहरीले रसायनों के अनियंत्रित उपयोग पर सख्त कार्रवाई, निगरानी और जागरूकता अभियान चलाने की मांग तेज कर दी है।

FOLLOW UP

गिद्धों की मौत क्यों है बड़ा खतरा?

गिद्ध प्राकृतिक रूप से मृत पशुओं का निस्तारण करते हैं। इनके कम होने से सड़े शव लंबे समय तक खुले रहते हैं, जिससे संक्रमण, बैक्टीरिया और आवारा जानवरों की संख्या बढ़ने का खतरा पैदा होता है। विशेषज्ञ इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से भी जोड़ रहे हैं।

कार्बोफ्यूरान पर बढ़ी निगरानी की मांग

कार्बोफ्यूरान को दुनिया के सबसे जहरीले कृषि रसायनों में गिना जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बिक्री और उपयोग की निगरानी कमजोर है। अब इस घटना के बाद कृषि और वन विभाग के संयुक्त अभियान की मांग तेज हो गई है।

भाजपा होगी फिर हिट या सपा करेगी वापसी?

विधानसभा चुनाव की हलचल तेज

राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटे दावेदार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल अपने-अपने स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट भी इस बार खास चर्चा में बनी हुई है। कभी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही यह सीट पिछले दो चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। खास बात यह है कि भाजपा का टिकट बदलाव फार्मूला यहां लगातार सफल साबित हुआ है।

» 2017से लगातार टिकट बदलने पर भाजपा को मिली सफलता

» सपा में पुराने चेहरों की वापसी से बदल सकते हैं समीकरण

वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई रसूलाबाद विधानसभा सीट पर हुए पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवकुमार बेरिया ने जीत दर्ज कर सपा का झंडा बुलंद किया था। विधायक बनने के बाद वह तत्कालीन सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे। उस चुनाव में भाजपा ने पूर्व सांसद कमलरानी वरुण को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें मात्र 24,974 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहीं। उस समय प्रदेश में भाजपा की स्थिति कमजोर होने के चलते पार्टी प्रत्याशी बसपा से भी पीछे रह गई थीं।

इसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। भाजपा ने बसपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुईं निर्मला संखवार पर दांव लगाया। भाजपा का यह फैसला सही साबित हुआ और निर्मला संखवार ने 88,390 वोट हासिल कर सपा प्रत्याशी अरुणा कोरी को हराकर पहली बार रसूलाबाद सीट भाजपा की झोली में डाल दी।

भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी टिकट परिवर्तन की रणनीति अपनाई। पार्टी ने मौजूदा विधायक निर्मला संखवार का टिकट काटकर 2017 में बसपा से चुनाव लड़ चुकीं पूनम संखवार को उम्मीदवार बनाया। भाजपा का यह प्रयोग भी सफल रहा और पूनम संखवार ने करीब 91,783 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इस तरह भाजपा ने लगातार दूसरी बार टिकट बदलकर भी सीट पर कब्जा बरकरार रखा।वर्ष 2012 से 2022 तक हुए तीन विधानसभा चुनावों में एक बार समाजवादी पार्टी और दो बार भाजपा को जीत मिली है। अब सभी की नजरें 2027 विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। भाजपा जहां लगातार तीसरी जीत के साथ हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई सीट वापस पाने की रणनीति बनाने में जुटी है।राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो रसूलाबाद विधानसभा में जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में मजबूत माने जाते हैं, लेकिन कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण समाजवादी पार्टी का प्रभाव भी यहां कम नहीं है। सपा यदि किसी अनुभवी और मजबूत चेहरे को मैदान में उतारती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है।

फिलहाल दोनों प्रमुख दल पूरी सक्रियता के साथ क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं।

भाजपा में टिकट को लेकर मंथन शुरू हो चुका है, जबकि सपा भी संगठन और पुराने जनाधार को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा एक बार फिर टिकट बदलाव के अपने पुराने फार्मूले पर भरोसा जताती है या इस बार कोई नया राजनीतिक प्रयोग देखने को मिलेगा।

2022 में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी पूनम संखवार

2012 में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहीं कमलरानी वरुण

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से लड़ीं प्रत्याशी निर्मला संखवार

मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में उमड़े मरीज बुखार के मामलों ने बढ़ाई चिंता

47 मरीजों की हुई जांच, डॉक्टरों ने गर्मी से बचाव के बताए उपाय

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर कस्बे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों की भीड़ देखने को मिली। मेले में कुल 47 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें 29 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल रहीं।

डॉ. शिव विनायक त्रिपाठी की मौजूदगी में आयोजित स्वास्थ्य मेले में डॉ. हरदीप सिंह समेत दो चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। जांच के दौरान सबसे अधिक मरीज बुखार से पीड़ित पाए गए। चिकित्सकों ने खून की जांच कराने के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं।

भीषण गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि बाहर का खाना खाने से बचें, अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। साथ ही उल्टी-दस्त जैसी समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचार कराने की बात कही।

डॉक्टरों ने बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की भी हिदायत दी। मेले के दौरान फार्मासिस्ट भोलेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ लिपिक नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के लिए पहुंचे डॉ. एच खान ने अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने पर स्वास्थ्य मेले में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए।

'पन्नी खोजो अभियान' के तहत रहीम

नगर वार्ड में चला विशेष सफाई अभियान

» नगर पंचायत कर्मचारियों ने जुटाई पॉलीथीन व पन्नी, लोगों को किया जागरूक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। नगर पंचायत रसूलाबाद द्वारा चलाए जा रहे 'पन्नी खोजो अभियान' के तहत रहीम नगर वार्ड में विशेष सफाई एवं जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर पंचायत कर्मचारियों ने वार्ड की गलियों और नालियों में फैली पॉलीथीन व पन्नियों को एकत्रित किया तथा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया।

नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कुल कमल सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगर क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त बनाना और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अभियान के तहत कर्मचारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर पॉलीथीन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी।

ईओ कुल कमल सिंह ने बताया कि पॉलीथीन का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इससे जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है, वहीं नालियों में कूड़ा जमा होने से जलभराव और गंदगी की समस्या भी बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के सभी वार्डों में यह अभियान लगातार 15 दिनों तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान लोगों को कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

साथ ही दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की हिदायत भी दी जा रही है। नगर पंचायत कर्मचारियों ने अभियान के दौरान नालियों की सफाई भी कराई, जिससे जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो सके। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए, ताकि नगर में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

नौबस्ता पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग दबोचा, 13 चोरी की बाइक-स्कूटी बरामद

डीसीपी साउथ और नौबस्ता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, तीन शातिर गिरफ्तार; चोरी के वाहनों के पार्ट्स काटकर बेचता था गैंग

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर कमिश्नरेट की नौबस्ता थाना पुलिस ने डीसीपी साउथ और एडिशनल डीसीपी साउथ के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलीम, सानू और वाजिद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जिनमें मोटरसाइकिल और स्कूटी शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद किए गए 13 वाहनों में से 8 वाहनों के संबंध में कानपुर कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बाकी वाहनों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय होकर शहर समेत आसपास के जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह का एक सदस्य शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों से मोटरसाइकिल व स्कूटी चोरी करता था। इसके बाद दूसरा आरोपी चोरी के वाहनों में तकनीकी बदलाव करने और उन्हें छिपाने का काम करता था। वहीं सानू, जो कबाड़ी का काम करता है, चोरी के वाहनों को कटवाकर उनके पार्ट्स अलग-अलग बेचता था। कुछ वाहनों को फर्जी तरीके से तैयार कर अवैध रूप से बेचने की भी जानकारी सामने आई है।

अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आरोपी सलीम और सानू के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 15 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

अनुदेशकों को बड़ी सौगात, मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार

» राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल बोले, सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए उनका मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से जनपद के अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत सिंह पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और शिक्षकों व अनुदेशकों के सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के हजारों अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी है। राज्यमंत्री ने कहा कि मानदेय वृद्धि से अनुदेशकों का मनोबल बढ़ेगा और विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। साथ ही 5 लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आर्थिक राहत भी मिलेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूनम संखवार ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से अनुदेशकों में उत्साह का माहौल है। भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कहा कि मानदेय वृद्धि से अनुदेशक अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। उन्होंने सभी अनुदेशकों को बधाई देते हुए शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक द्विवेदी ने किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में अनुदेशक उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

पीडब्ल्यूडी जल्द करायेगा खुले नाले में बैरीकेडिंग कार्य

राजपुर में खुले नाले का निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर कस्बे की पुलिस चौकी के सामने मुगल सड़क किनारे लगभग 25 बर्ष पहले बनाए गये नाले की क्षतिग्रस्त हुई पुलिया निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। उम्मीद है जल्द ही खुले नाले के आसपास बैरीकेडिंग कार्य करा दिया जाएगा ?

राजपुर कस्बे में मुगल सड़क किनारे प्रमुख बाजार है। सैकड़ों गांवों के लोग कस्बे की बाजार में नियमित खरीददारी करते हैं। पुलिस चौकी के सामने मुगल सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए गये नाले की पुलिया टूटने से व्यापारियों को हादसे का डर सता रहा था। आसपास के दुकानदार दीपू वाजपेई, चांद बाबू, कमलेश आदि का कहना है कि कई बार छुट्टा मवेशी और साइकिल सवार लोग नाले में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। व्यापारी काफी समय से नाले की मरम्मत कराने बनाने की मांग कर रहे हैं । विभिन्न समाचारों में खबर कोदिखाया इसके बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी। रविवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने खुले नाले वाले स्थान का निरीक्षण कर हकीकत परखी। व्यापारीयों ने अधिकारियों को खुले नाले से होने वाली समस्या बताई। इसके बाद अधिकारियों ने जल्द नाले की पुलिया की मरम्मत का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई प्रवीन कुमार बताया कि जल्द ही नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कराई जायेगी।

पंचायत चुनाव 2027 के बाद तय!

योगी कैबिनेट ने ओबीसी आयोग गठन को दी मंजूरी

लखनऊ मेट्रो विस्तार समेत 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता भी बढ़ा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में नए मंत्री भूपेन्द्र चौधरी और मनोज पांडेय भी शामिल हुए। कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आयोग का गठन और वेटनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और इसका कार्यकाल छह महीने का होगा। आयोग नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराए जा सकते हैं।

दरअसल, 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठन का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम के तहत स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आयोग का गठन किया गया है।

सरकार का मानना है कि बिना आयोग की रिपोर्ट के आरक्षण लागू करने पर मामला अदालत में फंस सकता था और चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती थी।

आयोग तीन प्रमुख कार्य करेगा। पहला, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पिछड़ी जातियों की आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाएगा। दूसरा, यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो। तीसरा, हर निकाय में ओबीसी आबादी के अनुपात के अनुसार आरक्षित सीटों की संख्या तय करेगा।कैबिनेट ने पशु चिकित्सा के छात्रों को भी बड़ी राहत दी।

ट्रिपल टेस्ट क्यों बना पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले राज्यों को ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें पिछड़े वर्ग की वास्तविक आबादी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की सीमा का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। इसी वजह से यूपी सरकार को आयोग गठित करना पड़ा।

2027 तक क्यों खिसक सकते हैं पंचायत चुनाव

ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का समय मिलेगा। इसके बाद आरक्षण निर्धारण, सीटों का पुनर्गठन और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होगी। माना जा रहा है कि यह पूरी कवायद विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूरी होना मुश्किल है। ऐसे में पंचायत चुनावों का कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है।

वेटनरी छात्रों को राहत, पशुपालन क्षेत्र को मिलेगा फायदा

इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार करने का फैसला वेटनरी छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे छात्रों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

बीवीएससी एंड एएच पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का मासिक भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। प्रदेश में हर वर्ष करीब 2 से 2.5 हजार छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, जबकि कुल मिलाकर 10 हजार से अधिक छात्र वेटनरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

गौरतलब है कि यूपी में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25-26 मई 2026 तक समाप्त हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन आयोग गठन और आरक्षण प्रक्रिया के चलते अब इसमें देरी तय मानी जा रही है।

जालौन डीएम के सख्त तेवर, अफसरों में मचा हड़कंप

» सम्पूर्ण समाधान दिवस में 41 शिकायतें पहुंचीं, 12 का मौके पर निस्तारण

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उरई/जालौन। जनसमस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने एक बार फिर सख्त प्रशासनिक रवैये का परिचय दिया। शनिवार को उरई तहसील सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

समाधान दिवस में डीएम के तेवर देखकर कई विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि जनता की शिकायतों में हीलाहवाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या शॉर्टकट अपनाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनें।

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने भी फरियादियों की शिकायतें सुनीं और थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि शिकायतों को लंबित रखने की प्रवृत्ति बंद करें तथा मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को राहत प्रदान की गई। शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

इस दौरान सीडीओ केके सिंह, एसडीएम ज्योति सिंह, सीएमओ डॉ. वीरेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पारदर्शिता के साथ जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।

सुल्तानपुर बिजली विभाग में

‘फर्जी शिकायत गैंग’ बेनकाब?

न शिकायतकर्ता का पता, न आरोपों का आधार फिर भी ईमानदार कर्मचारी को बदनाम करने की साजिश!

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या मंडल के सुल्तानपुर जनपद में बिजली विभाग इन दिनों बिजली कम और फर्जी शिकायत उद्योग को लेकर ज्यादा चर्चाओं में है। कार्यकारी सहायक पंकज कुमार सेठ के खिलाफ जिस शिकायत को आधार बनाकर जांच कमेटी गठित की गई, अब उसी शिकायत की साख कटघरे में खड़ी हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता का स्पष्ट पता तक मौजूद नहीं है। यानी एक संदिग्ध शिकायत, कुछ कागजी आरोप और अखबार में छपी खबर के आधार पर विभाग ने जांच बैठा दी।

सूत्रों के मुताबिक जांच समिति के अध्यक्ष खुद अनौपचारिक बातचीत में एक नहीं बल्कि तीन बार स्वीकार चुके है कि बिल संशोधन नियमानुसार हुआ और उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बावजूद जांच जारी है। अब सवाल उठ रहा है कि जब प्रथम दृष्टया कोई गड़बड़ी मिली ही नहीं तो आखिर यह जांच किस दबाव में चलाई जा रही है? चर्चा है कि विभाग में हावी दलाल कंपनी और बिलिंग एजेंसी तब बौखला गई जब कथित भ्रष्ट खेल में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद कार्यकारी सहायक को बदनाम और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की पटकथा लिखी गई।

पुराने आरोपों की धूल झाड़कर फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी तरह की शिकायत कराई गई थी, जिसमें पंकज सेठ जांच में निर्दोष पाए गए थे।

उनके ईई ऑफिस अटैचमेंट को भी कार्रवाई बताकर प्रचारित किया गया, जबकि हकीकत में स्वास्थ्य कारणों और व्यक्तिगत अनुरोध पर उन्हें संबद्ध किया गया था। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा पंकज सेठ पर पहले हमला भी हो चुका है।

जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी थी। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे सवाल उठ रहा है कि आखिर दबंगों और फर्जी शिकायतकर्ताओं को संरक्षण कौन दे रहा है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है–बिजली विभाग में निष्पक्ष जांच हो रही है या फिर किसी ईमानदार कर्मचारी की छवि खत्म करने का प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है?

सरयू ने छीन लिए गांव के तीन लाल, मचा कोहराम

» एक साथ उठीं तीन अर्थियां तो रो पड़ा पूरा तहसीनपुर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र के तहसीनपुर गांव में रविवार का दिन मातम बनकर उतरा। सरयू नदी में डूबे तीन किशोरों के शव जब एक-एक कर बाहर निकाले गए तो पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। जिन घरों में कल तक बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ मातम और सन्नाटा पसरा है। शनिवार शाम गांव के सत्यम पांडेय, मानस पांडेय, अमित पांडेय उर्फ राज, ध्रुव पांडेय और अंश पांडेय सरयू नदी में स्नान करने गए थे। नहाते समय मानस अचानक गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्त को बचाने के लिए सत्यम और अमित बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद पड़े। लेकिन सरयू की तेज धारा तीनों को अपने साथ बहा ले गई।

पूरी रात एसडीआरएफ, गोताखोर और पुलिस जाल डालकर तलाश करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार दोपहर एक-एक कर तीनों किशोरों के शव बरामद हुए तो परिजनों का कलेजा फट पड़ा।

26 मई को जिला मुख्यालय पर सपा का बड़ा प्रदर्शन

» महंगाई, जमीन अधिग्रहण और पेड़ कटान को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद करेंगे नेतृत्व

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। समाजवादी पार्टी 26 मई को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा सांसद अवधेश प्रसाद करेंगे। पार्टी ने महंगाई, किसानों की जमीन अधिग्रहण और अयोध्या में बिना मुआवजा लोगों के घर उजाड़ने के मुद्दे पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने का ऐलान किया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग निर्माण के नाम पर किसानों की जमीन जबरन ली जा रही है और बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसे लेकर पार्टी आंदोलन करेगी।इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्णकार समाज को कानून बनाकर व्यवस्था देने का आश्वासन दिया है।सपा सांसद राजकुमार भाटी की ब्राह्मणों पर टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मण देवतुल्य हैं और अखिलेश यादव सभी समाजों का सम्मान करते हैं।

टेंडर के चार टुकड़े, ठेका फिर भी एक ही जेब में!

» नगर निगम के बंगला नंबर-06 सुंदरीकरण में 35 लाख के खेल पर उठे सवाल, अभियंत्रण विभाग की भूमिका संदिग्ध

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।रामपथ स्थित मंडलायुक्त आवास के सामने बने नगर निगम के बंगला नंबर-06 के सुंदरीकरण में बड़ा खेल सामने आने की चर्चा है। आरोप है कि करीब 35 लाख रुपये के कार्य को ई-टेंडर प्रक्रिया से बचाने के लिए चार हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चारों टुकड़ों का काम आखिरकार एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया।

सूत्र बताते हैं कि यदि अलग-अलग फर्मों को कार्य मिलता तो शायद मामला दबा रहता, लेकिन पूरे खेल ने नगर निगम के अभियंत्रण विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल बंगले के सुंदरीकरण या निर्माण कंपनी पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर है जिसमें नियमों को ÷कागजी जुगाड़÷ से साधने की कोशिश दिखाई दे रही है।

यह पहला मामला नहीं है। चार वर्ष पूर्व त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत नगर निगम सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में सड़क और नाली निर्माण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत हुए थे। आरोप है कि कई स्थानों पर नालियां बनी ही नहीं, लेकिन आरटीआई के जवाब में निर्माण पूरा दिखा दिया गया। बनवीरपुर रेलवे क्रॉसिंग मार्ग इसका उदाहरण बताया जा रहा है।अब सवाल यही है कि नगर निगम में टेंडर और निर्माण का खेल आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? और हर बार फाइलों में विकास दिखाकर जमीन पर सिर्फ धूल क्यों उड़ती है?

स्कॉर्पियो छोड़ी, लेकिन पीछे दौड़ पड़ा तीन बाइकों का काफिला!

भाजपा जिलाध्यक्ष की ‘ईंधन बचत यात्रा’ पर सवाल, बिना पीयूसी बुलेट पर परिवहन विभाग की चुप्पी चर्चा में

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं और अयोध्या में भाजपा जिलाध्यक्ष उस अपील का ऐसा ÷अनुपालन÷ कर रहे हैं, जिसने लोगों को गणित लगाने पर मजबूर कर दिया है। पहले स्कॉर्पियो से चलने वाले जिलाध्यक्ष महोदय अब बुलेट बाइक पर नजर आते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्र बताते हैं कि उनके साथ दो नहीं, बल्कि तीन मोटरसाइकिलों का पूरा काफिला चलता है।अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इससे ईंधन की बचत हो रही है या खपत पहले से ज्यादा बढ़ गई है? लोग तंज कस रहे हैं कि स्कॉर्पियो गई, लेकिन पेट्रोल तीन टंकियों में बंट गया।मामले का दूसरा और

ज्यादा दिलचस्प पहलू परिवहन विभाग की कार्यशैली को लेकर है। चर्चा है कि भाजपा जिलाध्यक्ष जिस बुलेट बाइक से चलते हैं उसका पीयूसी सर्टिफिकेट अक्टूबर 2024 से समाप्त है। आम आदमी का पीयूसी न होने पर हजारों रुपये का चालान काटने वाला

Vehicle Number	UP42BP3939
Owner Name	V****H P****K
Registering Authority	AYODHYA RTO, Uttar Pradesh
Vehicle Class	M-Cycle/Scooter(2WN)
Fuel Type	PETROL
Emission Norm	BHARAT STAGE VI
Vehicle Age	2 Years & 6 months
Hypothecated	Yes
Vehicle Status	ACTIVE
Tap to Check the impound/seizure document status	
Registration Date	25-Oct-2023
Fitness Valid UpTo	24-Oct-2038
Tax Valid UpTo	LTT
Insurance Valid UpTo	19-Oct-2028
PUCC Valid Upto	24-Oct-2024

परिवहन विभाग यहां पूरी तरह मौन दिखाई दे रहा है।जनता सवाल पूछ रही है कि क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? और क्या सत्ता की नंबर प्लेट लगते ही प्रदूषण भी राष्ट्रहित में माफ हो जाता है? अब निगाहें परिवहन विभाग पर हैं कि वह कार्रवाई करेगा या मेहरबानी का इंजन यूं ही चलता रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति की नई चेतावनी से मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव

ट्रंप की दो टूक: यूरेनियम पर फैसला करो, नहीं तो मिट जाएगा ईरान का वजूद

परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका-ईरान टकराव खतरनाक मोड़ पर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक बार फिर ईरान को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के पास अब समय बहुत कम बचा है और उसे यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) को लेकर तुरंत फैसला लेना होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि ईरान ने जल्द कदम नहीं उठाया, तो 'दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिट सकता है।'

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव लगातार चरम पर पहुंच रहा है। बीते कई महीनों से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत ठप पड़ी है और पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां भी तेज हुई हैं। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ईरान तेजी से उच्च स्तर का यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जिससे परमाणु हथियार निर्माण की आशंका बढ़ रही है।

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अब 'अनंत इंतजार' नहीं करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज किया, तो अमेरिका कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने सीधे सैन्य कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों को बेहद सख्त चेतावनी माना जा रहा है। ईरान की ओर से अभी तक ट्रंप के बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तेहरान पहले भी साफ कर चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और दबाव उसकी संप्रभुता पर हमला हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति नहीं, बल्कि आगामी अमेरिकी विदेश नीति की झलक भी हो सकता है। मध्य-पूर्व में पहले से जारी संघर्ष, इजराइल-हमास युद्ध और तेल आपूर्ति को लेकर वैश्विक चिंता के बीच यह बयान अंतरराष्ट्रीय बाजारों और सुरक्षा समीकरणों पर असर डाल सकता है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने पहले भी अमेरिका और ईरान से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन ट्रंप के ताजा बयान के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि यदि बातचीत की कोई नई पहल नहीं हुई, तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं।

- ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर ईरान को सीधी चेतावनी दी।
- अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पर कड़ा रुख अपनाया।
- ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बता रहा है।
- मध्य-पूर्व में सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका।
- वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने पहले भी संयम बरतने की अपील की थी।
- इजराइल-ईरान तनाव भी अमेरिकी नीति को प्रभावित कर रहा है।
- आने वाले दिनों में नई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई संभव मानी जा रही है।

ट्रंप की नीतिः 'दबाव बनाओ और झुकाओ'

डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान पर 'मैक्सिमम प्रेशर' नीति लागू कर चुके हैं। आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक और सैन्य चेतावनियां उनकी रणनीति का हिस्सा रही हैं। नया बयान उसी आक्रामक नीति की अगली कड़ी माना जा रहा है।

दुनिया की नजर अगली कूटनीतिक चाल पर

संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों की नजर अब इस बात पर है कि क्या दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू होगी या हालात टकराव की ओर बढ़ेंगे। आने वाले कुछ सप्ताह निर्णायक माने जा रहे हैं।

इजराइल फैक्टर भी बना बड़ा कारण

इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका पर इजराइल का दबाव भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बड़ी वजह है।

यूरेनियम संवर्धन क्यों बना विवाद की जड़?

यूरेनियम संवर्धन परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों के लिए अहम प्रक्रिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान इसी तकनीक का इस्तेमाल हथियार निर्माण की दिशा में कर सकता है, जबकि ईरान इसे ऊर्जा जरूरतों से जोड़ता है।

मध्य-पूर्व में बढ़ सकता है सैन्य तनाव

विशेषज्ञों के मुताबिक मेरिका-ईरान तनाव और बढ़ा, तो खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इसका असर तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

विधानसभा में 'सनातन को खत्म करना होगा' बयान पर अवमानना याचिका दाखिल, पुलिस कार्रवाई न होने पर उठे सवाल

सनातन टिप्पणी पर फिर घिरे उदयनिधि, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर कानूनी घेरे में आ गए हैं। विधानसभा के भीतर दिए गए उनके बयान को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरोप है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान कहा था कि 'सनातन को खत्म करना ही होगा।' इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।

मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित हेट स्पीच संबंधी मामले से जोड़ दी गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

यह याचिका 'शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ' मामले से जुड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को हेट स्पीच मामलों में स्वत: एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अधिवक्ता ने अदालत से मांग की है कि आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हुए इसे 'समाप्त करने' की बात कही थी। उस बयान पर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और भाजपा सहित कई संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई थी।

हालिया विवाद के बाद उदयनिधि ने सफाई देते हुए कहा कि उनका विरोध किसी धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं है, बल्कि जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि द्रविड़ आंदोलन सामाजिक समानता और भेदभाव के विरोध की विचारधारा से निकला है। उन्होंने कहा कि 'जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए' का अर्थ धर्म विरोध नहीं है। उनका कहना था कि सभी लोगों को मंदिरों और समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों ने उनकी सफाई को राजनीतिक बचाव बताते हुए तीखा हमला बोला है।

क्या था उदयनिधि का बयान

सितंबर 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का केवल विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। इस बयान के बाद देशभर में भारी विवाद खड़ा हुआ था और कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com